DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023 ...ATED-----------------

यमुना की प्रदूषण व्यथा रह-रहकर उठती है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दो कदम सुधार के बढ़ते भी हैं तो वे दिखाई नहीं देते। वास्तव में जब तक बड़े नाले यमुना के साथ जुड़े रहेंगे या इसमें गिरते रहेंगे, तब तक ऐसे ही हालात रहेंगे। शोधन की प्रक्रिया बहुत धीमी है। दिल्ली में जिस तेजी से आबादी बढ़ी है और उसने जो कचरा पैदा किया है, उसने यमुना के पानी को जहरीला बना दिया है।

यमुना का 'रिवर' भरा है 'सीवर'

नालों की लंबाई

निर्मित
3,311.54 किमी

प्राकृतिक
426.55 किमी

कितने नाले कहां

प्राकृतिक 201

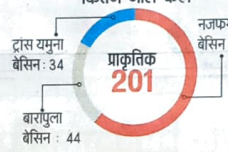

- ट्रांस यमुना बेसिन : 34
- नजफगढ़ बेसिन : 123
- बारापुला बेसिन : 44

शोधन को लेकर क्या है स्थिति

- शोधन संयंत्र 35
- उत्पन्न सीवरेज 768
- शोधन क्षमता 632
- शोधन हो रहा 573.5
- बगैर शोधन के यमुना में गिर रहा है सीवरेज 194.5

नोट : एमजीडी में

यमुना में गिरने से पहले शोधन के प्रयास

- शोधित नाले : 13
- पानी की मात्रा : 58 .75 एमजीडी
- कुछ हिस्सा रोक कर किया जा रहा शोधित : 2
- इसमें कितना शोधन हुआ : 230 एमजीडी
- दो नालों का पानी नहीं हो रहा है ट्रैप : 313 एमजीडी
- पानी यमुना में गिरने से पहले नहीं होता ट्रैप : 3

वजीराबाद से ओखला

गिरने वाले नाले	नालों से गिरने वाला पानी	पानी की मात्रा, जिसे किया जाता है ट्रैप	अभी नहीं हो रहा है ट्रैप
18	664.35	288.75	375.6

नोट : एमजीडी

इंटरसेप्टर सीवर लाइन सिस्टम

- छोटे नाले : 108
- पानी को रोक कर शोधन की तैयारी : 242 एमजीडी
- ट्रैप किया जा रहा नालों का पानी : 238 एमजीडी
- लाइन रोक कर सीवरेज युक्त पानी का शोधन : 230 एमजीडी

दिल्ली का सबसे बड़ा नजफगढ़ नाला

- नालों की लंबाई : 57 .489 किमी
- पानी का प्रवाह : 453 एमजीडी
- जल प्रवाह में सीवरेज शोधन संयंत्र से शोधित पानी का हिस्सा : 252 एमजीडी
- इसे नाले में सीवरेज का पानी गिरने से पहले इंटरसेप्टर सीवर लाइन से शोधन के लिए किया जा रहा है ट्रैप : 172 एमजीडी

एजेंसियां : नालों का दायरा

एजेंसी	लंबाई
सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग	426.55
लोक निर्माण विभाग	2064.08
दिल्ली नगर निगम	521.87
दिल्ली विकास प्राधिकरण	251.30
डीएसआइआइडीसी	98.12
दिल्ली कैंट बोर्ड	39.68
एनटीपीसी	3.11

नोट : नालों की लंबाई किमी में

जागरण इन्फो

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 4 जनवरी 2023

डीडीसीए

अजय का दमदार खेल

अजय गुलिया (55* रन और 4/33) शानदार ऑलराउंड खेल और शिवम कन्नौजिया (55) व अथर्व गुप्ता (2/30) के अहम योगदान से टाइम्स ऑफ इंडिया (204) ने तिलक नगर कोल्ट्स (192/10) को 12 रन से हरा दिया।

अंकुर का शतक

अंकुर (128*) के उम्दा शतक और प्रदीप साहू (22 रन, 1/55), अभिनव (2/39) की मदद से दिल्ली ऑडिट (266/6) ने रोहतक रोड जिमखाना (265/4) को चार विकेट से हरा दिया। रोहतक रोड की ओर से सुमित माथुर (110*) और ध्रुव कौशिक (92) ने भी शानदार पारी खेली।

दिल्ली पुलिस जीती

सुनील सहवाग (66), अरुण कटारिया (33 रन, 1/28) और सचिन मान (2/33) के प्रयास से दिल्ली पुलिस (195/8) ने पीएमजी क्लब (127/7) को 18 रन से हराया।

शाश्वत का उम्दा खेल

शाश्वत कोहली (3/14 और 14* रन), अभिषेक रंजन (3/27) और मानव चावला (70*) के शानदार खेल की मदद से डीडीए (145/2) ने एलबी शास्त्री सीसी (144/10) को 8 विकेट से हरा दिया।

अभिषेक, हार्दिक की फिफ्टी

अभिषेक अग्रवाल (74) और हार्दिक (51) की फिफ्टी और चंद्रेश ठाकुर (3/33) व सौद करीम (2/29) के प्रयास से मलिक स्पोर्ट्स (253/3) ने पीएनबी (248/8) को सात विकेट से हरा दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER दैनिक जागरण नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023 -DATED----------

टास्क फोर्स गठित कर चलाना होगा अभियान

आरएस त्यागी
पूर्व सदस्य, दिल्ली
जल बोर्ड

यमुना के मैली होने का एक बड़ा कारण नालों से बगैर शोधन के पानी गिरना है। नालों के पानी को यमुना में गिरने से पहले ही शोधित करने के प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं। भारी भरकम खर्च के बावजूद अब तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। नाले भी कई एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण दिक्कतें होती हैं। ऐसे में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में एक विशेष टास्क फोर्स गठित कर नालों के पानी और यमुना को साफ करने का अभियान चलाना होगा। इसका नेतृत्व केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा।

दिल्ली के बड़े इलाके में अभी सीवर लाइन का नेटवर्क नहीं है। इसलिए इंटरसेप्टर सीवर लाइन की परिकल्पना की गई थी कि नाले के साथ-साथ एक गहरी सीवर लाइन बिछाई जाए, जिससे नजफगढ़, सप्लीमेंट्री व शाहदरा ड्रेन में सीवरेज युक्त गंदा पानी गिराने वाले छोटे-छोटे नालों का पानी रोक कर इंटरसेप्टर सीवर लाइन में एकत्रित हो जाएगा और इस पानी को सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) ले जाकर शोधित किया जाए। शोधित करने के बाद ही पानी को नाले में गिराया जाए।

दिल्ली जल बोर्ड ने इंटरसेप्टर सीवर लाइन तो बिछा दी, लेकिन जिस एसटीपी में नालों का पानी ले जाकर शोधित किया जाना है, वे एसटीपी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए केशोपुर में 20 और 40 एमजीडी के दो संयंत्र (कुल क्षमता 60 एमजीडी) ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बगैर शोधन के ही सीवरेज का पानी आगे नाले में बहाया जाता है। इसी तरह कई एसटीपी का नवीनीकरण कर शोधन क्षमता बढ़ानी थी, यह काम अभी पूरा नहीं हुआ। कोरोनेशन पिलर में 70 एमजीडी का नया एसटीपी बनकर तैयार हुआ है, वहां भी अभी क्षमता के अनुरूप पूरा सीवरेज नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा नगर निगम का ठोस कचरा प्रबंधन भी सही नहीं है। जब तक इन चीजों पर रोक नहीं लगेगी, तब तक नालों के पानी को साफ कर पाना संभव नहीं है।

इंटरसेप्टर सीवर लाइन की योजना भी वर्ष 2008 के आसपास तैयार हुई थी, उस वक्त नजफगढ़, सप्लीमेंट्री व शाहदरा नाले में 108 छोटे नालों का पानी गिरता था। इंटरसेप्टर सीवर लाइन की डिजाइन करीब डेढ़ दशक पहले की जरूरत के अनुसार तैयार की गई थी। वर्ष 2011 में इसका काम शुरू हुआ था और 11 वर्ष के बाद यह तैयार हुई। इस दौरान कई छोटे-छोटे नाले बन गए और मौजूदा समय में नजफगढ़, सप्लीमेंट्री व शाहदरा इन तीन प्रमुख नालों में 200 से अधिक छोटे नालों का गंदा पानी गिरता है, जबकि इंटरसेप्टर सीवर लाइन से 108 नालों के पानी को ही ट्रैप किया जा सकता है। 700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन अभी हर घर में सीवर का कनेक्शन नहीं हो पाया है। नाले भी मुख्य रूप से तीन विभागों में बटे हुए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल हैं। ऐसे में यदि कोई एक विभाग अपने नालों की ठीक से सफाई नहीं करे तो दो एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य का भी फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए सभी नाले एक ही एजेंसी के पास होने चाहिए। उपराज्यपाल के अधीन वर्ष 2012 में यमुना विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, लेकिन इस पर खास कार्य नहीं हुआ। इसे फिर से सक्रिय करना होगा और डीडीए में विशेषज्ञों के नेतृत्व में विशेष टास्क फोर्स का गठन हो जो दिल्ली व एनसीआर के शहरों से संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर नालों व यमुना की सफाई के लिए कार्य करे। डीडीए के पास फंड का भी अभाव नहीं है।

-रणविजय सिंह से बातचीत पर आधारित

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 4 जनवरी 2023 TED----------

दिल्ली को क्यों लग रहे भूकंप के झटके

हाल के दिनों में दिल्ली और आसपास के दायरे में भूकंप के झटके बड़ी संख्या में आए हैं। साल 2020 में 51 बार धरती कांपी। ये झटके भले ही हलके हों, लेकिन बड़े खतरे का संकेत हैं

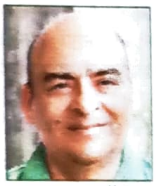

पंकज चतुर्वेदी

नए साल के जश्न में उस समय थोड़े भय की छाया आई, जब अचानक दिल्ली और आसपास की धरती थर्रा गई। बीते साल नवंबर में दो बार ऐसे भूकंप के झटके आए थे, जिनमें से एक अतिगंभीर की श्रेणी में था। साल 2020 में दिल्ली और उसके आसपास के दायरे में कुल 51 बार धरती थर्राई। ये झटके भले ही हलके हों, लेकिन बहुत बड़े खतरे का संकेत हैं। नैशनल सेंटर फार सिस्मॉलजी ने दिल्ली को खतरे के लिए तय जोन चार में आंका है। यानी यहां भूकंप आने की संभावनाएं गंभीर स्तर पर हैं।

क्यों खतरे में है दिल्ली: कोई 1482 वर्ग किलोमीटर में फैली राजधानी दिल्ली की आबादी सवा दो करोड़ के करीब है। एनसीआर को मिला लें तो सवा तीन करोड़ लोगों की इस बसावट का चालीस फीसदी हिस्सा अनधिकृत है और करीब 20 फीसदी बहुत पुराने निर्माण हैं। बाकी रिहाइशों में से बमुश्किल पांच प्रतिशत का निर्माण ऐसा है, जिसे भूकंपरोधी के रूप में सत्यापित किया जा सका है। सबसे बड़ी बात है महानगर की हर दिन बढ़ती आबादी में इस भयानक खतरे की प्रति जागरूकता की कमी।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटकों का कारण भूगर्भ से तनाव–ऊर्जा उत्सर्जन है। यह ऊर्जा अब भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में बढ़ने और फॉल्ट या कमजोर जोनों के जरिये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के चलते एकत्र हुई है। वाडिया इंस्टिट्यूट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में कई सारे कमजोर जोन और फॉल्ट हैं: दिल्ली–हरिद्वार रिज, महेंद्रगढ़–देहरादून उपसतही फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, दिल्ली–सरगोधा रिज, यमुना नदी लीनियामेंट आदि। नए साल के भूकंप का केंद्र महेंद्रगढ़ ही था।

यमुना और हिंडन: सन 2016 में भारत सरकार के नैशनल सेंटर फॉरर सिस्मॉलजी ने कोई 450 स्थानों पर गहन शोध कर भूकंप की आशंका पर एक रिपोर्ट जारी की थी। 'ए रिपोर्ट ऑन सेस्मिक हजार्ड : माइक्रो जोनेशन ऑफ एनसीटी दिल्ली' नाम की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एक तो दिल्ली दुनिया के सबसे युवा पहाड़ हिमालय के बहुत करीब है और

कॉमन रूम

दूसरे यह अरावली पर्वतमाला के अंतिम सिरे पर है। दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता इसकी बसावट का आधे से ज्यादा हिस्सा यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बसा होना है। खासकर गांधीनगर से लेकर ओखला तक बसी आबादी तो यमुना की दलदल पर ही बसी है और यह पूरा सघन आबादी वाला बहुमंजिला इमारतों का क्षेत्र है। ठीक यही हाल गाजियाबाद और नोएडा की नई गगनचुंबी इमारत वाली बस्तियों का है जो कि हिंडन या यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में बसा दी गई हैं।

रास्ता नहीं भूलती नदी: जान लें कि कोई भी नदी अपना रास्ता दो सौ साल तक नहीं भूलती। आज नदी का रस्ता बदलने से खाली हुई जमीन पर यदि पक्का निर्माण कर लिया तो दो सदी में कभी भी नदी अपनी जमीन वापस मांग सकती है। इसका मूल कारण है कि भले ही सीमेंट पोत कर धरती का ऊपरी कायाकल्प कर लें, उसकी भीतरी परत, उसके भीतर की भूगर्भीय संरचना बदलती नहीं। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद के एक शोध से स्पष्ट हुआ है कि भूकंप का एक बड़ा कारण धरती की कोख से जल का अंधाधुंध दोहन करना भी है। भूजल धरती के भीतर लोड यानी कि एक भार के तौर पर उपस्थित होता है। इसी लोड के चलते फॉल्ट लाइनों में भी संतुलन बना रहता है। बाहरी दिल्ली में वे इलाके भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील माने गए हैं, जहां भूजल बहुत ही नीचे चला गया है।

आज जरूरत है कि दिल्ली में आबादी का घनत्व कम करने की, जमीन पर मिट्टी की ताकत मापे बगैर कई मंजिला भवन खड़े करने और बेसमेंट बनाने पर रोक लगाई जाए और भूजल के दोहन पर सख्ती हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि राजधानी में 42 लाख से अधिक भवनों को भूकंपरोधी रेट्रोफिटिंग करवाई जाए। साल 2012 में डीडीए में इसकी योजना भी बनी थी, रेट्रोफिटिंग के लिए ही एक अलग डिविजन बनाने की बात थी, लेकिन इसके बाद यह काम फाइलों में दब गया।

लड्डा सराय फॉरेस्ट मामला : डीडीए के खिलाफ लामबंद होने लगे लोग

■ एनबीटी न्यूज, महरौली

लड्डा सराय फॉरेस्ट एरिया डिमार्केशन मामले में प्रभावित फ्लैट मालिक लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाकर सरकार और डीडीए की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। पिछले दिनों हुई मीटिंग में 600 से अधिक लोग शामिल हुए थे।

बैठक में काफी विचार करने के बाद आंदोलन के लिए 'जन संघर्ष समिति' का गठन किया गया है। समिति के माध्यम से सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचाने के लिए प्रतिनिधिमंडल सक्रिय किया गया। इसके तहत नुक्कड़ सभाएं करके प्रभावित लोगों के साथ क्षेत्र के अन्य संगठन, संस्थान और लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में सरकार के खिलाफ धरना व प्रदर्शन का दौर भी शुरू होगा। लोगों का कहना है कि सरकार और डीडीए की गलत नीतियों और कार्य करने के तरीकों के कारण हजारों परिवार बेघर होने के कगार पर हैं। इसमें वहां रहने वाले लोगों का दोष नहीं, बल्कि डीडीए की लापरवाही का कसूर है।

मीटिंग कर लगाए कई आरोप